पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

2018 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 325

में

2017 का दीवानी रिट अधिकारिता मामला संख्या 14930

=====

प्रो.चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर, श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव के पुत्र, क्वार्टर संख्या- 16/6, गजट (असेंबली पूल की एक ई श्रेणी), अधिकारी फ्लैट, बेली रोड, थाना- शास्त्रीनगर, जिला- पटना के निवासी।

2. विजय प्रकाश, श्री अखिलेश्वर प्रसाद यादव का पुत्र, क्वार्टर संख्या- 11, स्ट्रैंड रोड, थाना- सचिवालय, जिला-पटना का निवासी।

3. आलोक कुमार मेहता, तुलसीदास मेहता के पुत्र, क्वार्टर संख्या- 6, नेताजी सुभाष मार्ग, स्ट्रैंड रोड, थाना- सचिवालय, जिला-पटना के निवासी।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. संपदा अधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. सक्षम प्राधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

5. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पाटलिपुत्र प्रभाग, बिहार सरकार, पटना।

6. समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, पटना।

7. अपर जिला दंडाधिकारी, कानून व्यवस्था, पटना।

8. सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

..... उत्तरदातागण

के साथ

2018 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 326

2017 का दीवानी में रिट अधिकारिता मामला संख्या 14975

=====

1. चंद्रिका राय, स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय के पुत्र, गाँव + पोस्ट-बजियाँ के निवासी, थाना-दरियापुर, जिला-छापरा (सारण)
2. डॉ. अब्दुल गफूर, मोहम्मद जमाल के पुत्र, गाँव-भलाही बौहरवा के निवासी, डाकघर-भलाही, जिला-सहारसा
3. अनीता देवी, स्वर्गीय आनंद मोहन सिंह की पत्नी, ग्राम- अकाशी, डाकघर-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास के निवासी।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. संपदा अधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
3. बिहार विधान सभा पटना अपने सचिव के माध्यम से
4. अब्दुल बारी सिद्दीकी, स्वर्गीय अली अहमद के पुत्र, गाँव-रूपसपुर के निवासी, डाकघर-धामसैन, थाना- अलीनगर, जिला-दरभंगा के निवासी
5. शिव चंद्र राम, श्री प्रभु राम के पुत्र, गाँव के निवासी-महुआ, मुकुंदपुर, डाकघर + थाना- महुआ, जिला-वैशाली

..... उत्तरदातागण

=====

पटना उच्च न्यायालय का पत्र पेटेंट-खंड 10-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-नकारात्मक समानता की अवधारणा-बिहार विधान सभा सदस्य निवासी आवंटन नियम, 2000-नियम 13-रिट अदालत के उस आदेश को चुनौती जिसमें रिट अदालत ने दिनांकित 20.09.2017 के विवादित पत्रों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को सरकार में उनके मंत्री पद की समाप्ति के आधार पर क्वार्टर खाली करने और संबंधित विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया था-याचिका है कि डी एवं ई-प्रकार के क्वार्टर हैं जिन पर उनके द्वारा कब्जा कर लिया गया है। विधान सभा के कुछ सदस्य जो उन आवासों को प्राप्त करने या उन पर कब्जा करने के हकदार नहीं हैं, लेकिन विभाग द्वारा अवैध रूप से और मनमाने ढंग से आवंटित किए गए हैं।

आयोजित किया गया:अपीलार्थी की नकारात्मक समानता की याचिका विचाराधीन क्वार्टरों पर कब्जा जारी रखने के अपने अधिकार का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि अपीलार्थी उन क्वार्टरों के कब्जे के साथ बने रहने का कोई कानूनी अधिकार प्रदर्शित करने में असमर्थ हैं जो स्वीकार्य रूप से केंद्रीय पूल में आते हैं और केवल मंत्रियों को आवंटित किए जाते हैं-रिट अदालत ने पहले ही अपीलार्थियों की शिकायत को संबोधित कर दिया है कि कुछ अयोग्य व्यक्तियों को अवैध और मनमाने ढंग से आवंटन किया गया है जैसा कि अपीलार्थी-अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किया गया है।(पैरा 8,11)

ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 34, ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1937..... भरोसा किया ।

पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

2018 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 325

में

2017 का दीवानी रिट अधिकारिता मामला संख्या 14930

=====

प्रो.चंद्रशेखर उर्फ चंद्रशेखर, श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव के पुत्र, क्वार्टर संख्या- 16/6, गजट (असेंबली पूल की एक ई श्रेणी), अधिकारी फ्लैट, बेली रोड, थाना- शास्त्रीनगर, जिला- पटना के निवासी।

2. विजय प्रकाश, श्री अखिलेश्वर प्रसाद यादव का पुत्र, क्वार्टर संख्या- 11, स्ट्रैंड रोड, थाना- सचिवालय, जिला-पटना का निवासी।

3. आलोक कुमार मेहता, तुलसीदास मेहता के पुत्र, क्वार्टर संख्या- 6, नेताजी सुभाष मार्ग, स्ट्रैंड रोड, थाना- सचिवालय, जिला-पटना के निवासी।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. संपदा अधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. सक्षम प्राधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

5. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पाटलिपुत्र प्रभाग, बिहार सरकार, पटना।

6. समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, पटना।

7. अपर जिला दंडाधिकारी, कानून व्यवस्था, पटना।

8. सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

..... उत्तरदातागण

के साथ

2018 का पत्र पेटेंट अपील संख्या 326

2017 का दीवानी में रिट अधिकारिता मामला संख्या 14975

=====

1. चंद्रिका राय, स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय के पुत्र, गाँव + पोस्ट-बजियाँ के निवासी, थाना-दरियापुर, जिला-छापरा (सारण)
2. डॉ. अब्दुल गफूर, मोहम्मद जमाल के पुत्र, गाँव-भलाही बौहरवा के निवासी, डाकघर-भलाही, जिला-सहारसा
3. अनीता देवी, स्वर्गीय आनंद मोहन सिंह की पत्नी, ग्राम- अकाशी, डाकघर-मोकर, थाना-अगरेर, जिला-रोहतास के निवासी।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. संपदा अधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
3. बिहार विधान सभा पटना अपने सचिव के माध्यम से
4. अब्दुल बारी सिद्दीकी, स्वर्गीय अली अहमद के पुत्र, गाँव-रूपसपुर के निवासी, डाकघर-धामसैन, थाना- अलीनगर, जिला-दरभंगा के निवासी
5. शिव चंद्र राम, श्री प्रभु राम के पुत्र, गाँव के निवासी-महुआ, मुकुंदपुर, डाकघर + थाना- महुआ, जिला-वैशाली

..... उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थियों के लिए	:	श्री अभिनव श्रीवास्तव, अधिवक्ता
प्रतिवादियों के अधिवक्ता 11	:	श्री राज बल्लभ प्रसाद यादव- अपर महाधिवक्ता जवाब के लिए।
प्रतिवादी संख्या- 3 और 8 के लिए:		श्री पी. के. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता,
		श्री कौशल कु. सिंह, अधिवक्ता

=====

कोरम: मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद)

तारीख: 14-03-2018

इन दो लेटर्स पेटेंट अपीलस में चुनौती 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या- 14975/2017 और 2017 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या- 14930 में विद्वान न्यायालय द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 28.02.2018 के लिए है। रिट अदालत को यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के संपदा अधिकारी द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए दिनांक 20.09.2017 के पत्र में अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। हालाँकि, रिट अदालत ने याचिकाकर्ताओं को विचाराधीन क्वार्टरों को खाली करने और उन्हें बिहार सरकार के संबंधित भवन निर्माण विभाग को सौंपने के लिए पंद्रह दिनों की स्वीकृति प्रदान की।

2. रिट अदालत ने रिट याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए कि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति जो इसके हकदार भी नहीं हैं, प्रतिवादियों द्वारा किए गए मनमाने आवंटन के आधार पर विधायी पूल के तहत डी एंड ई प्रकार के क्वार्टरों के कब्जे में रहे हैं, पाया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से संबंधित नियमों के लिए इस तरह के मनमाने आवंटन के संबंध में कोई विशिष्ट खंडन नहीं था, इसलिए न्याय के उद्देश्य से, बिहार विधानसभा के सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे उन व्यक्तियों को विधायी पूल के तहत किए जा रहे क्वार्टरों के इस तरह के अवैध आवंटन का पता लगाएं जो इसके हकदार नहीं हैं और उसके बाद ऐसे आवासों को

खाली करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाना ताकि याचिकाकर्ताओं को उनकी पात्रता के अनुसार उनका आवंटन किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए अदालत ने संबंधित प्रतिवादी को 60 दिनों का समय दिया है।

3. परिवर्तित परिस्थितियों में, विद्वान रिट अदालत ने सचिव, बिहार विधानसभा को संबंधित नियमों के तहत एक ही प्रकार के क्वार्टर के लिए हकदार विधान सभा के सदस्यों की अंतर-पात्रता की जांच करने से प्रतिबंधित कर दिया, इस सरल कारण से इस तरह की कवायद का विषय नहीं हो सकता है कि याचिकाकर्ताओं का व्यक्तिगत दावा प्रासंगिक नियमों के तहत उनकी पात्रता के अनुसार विधानसभा पूल के तहत क्वार्टरों के आवंटन के बारे में संयोग से, राज्य में एक नई गठबंधन सरकार के गठन के बाद राज्य सरकार में उनके मंत्री पद की समाप्ति के कारण अर्जित हुआ है।

4. श्री अभिनव श्रीवास्तव, दोनों मामलों में अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता उसी क्वार्टर पर कब्जा करने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं जिसमें वे वर्तमान में रह रहे हैं, बल्कि अपीलकर्ताओं की शिकायत यह है कि ई-प्रकार के क्वार्टरों की श्रेणी अभी भी उपलब्ध है और/या उन लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है जो इसके लिए हकदार नहीं हैं, लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा किए गए मनमाने और अवैध आवंटन के कारण, अपीलकर्ताओं को अपने-अपने क्वार्टर खाली करने के लिए कहा जा रहा है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी बिहार विधान सभा सदस्य निवासी आवंटन नियम, 2000 (इसके बाद "नियम, 2000" के रूप में संदर्भित) नियम 13 में निहित प्रावधानों के सदर्थ में ई प्रकार के क्वार्टरों के हकदार हैं और वर्तमान में वे एक ही प्रकार के आवासों में रह रहे हैं।

5. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि डी और ई श्रेणी से संबंधित बड़ी संख्या में क्वार्टर उन सदस्यों को आवंटित किए गए हैं जो अन्यथा नियम 2000 के

उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में ऐसे क्वार्टरों के आवंटन के हकदार नहीं हैं। इस न्यायालय का ध्यान उन अधिभोगियों के विस्तृत विवरणों की ओर भी आकर्षित किया गया है जिन पर विद्वत रिट न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में ध्यान दिया है।

6. दूसरी ओर, श्री ललित किशोर, विद्वान महाधिवक्ता के साथ-साथ श्री पी. के. शाही, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपीलार्थियों के विद्वान वकीलों की दलीलों का विरोध किया है, क्योंकि उनके अनुसार, याचिकाकर्ता अब राज्य सरकार में मंत्री नहीं हैं, इसलिए उन्हें उन आवासों को खाली करना पड़ता है जो राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए केंद्रीय पूल के तहत निर्धारित हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विधानसभा के सदस्यों को आवासों का आवंटन भवन निर्माण विभाग द्वारा आवंटित नहीं किया जाता है। न्यायालय को सूचित किया गया है कि विचाराधीन क्वार्टर भवन निर्माण विभाग का केन्द्रीय पूल है और सभी क्वार्टर पहले से ही नई गठबंधन सरकार में मंत्रियों को आवंटित किए जा चुके हैं।

7. विद्वान महाधिवक्ता के साथ-साथ श्री पी. के. शाही, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं की शिकायत है कि डी-श्रेणी और ई-श्रेणी क्वार्टरों के क्वार्टर अवैध रूप से और मनमाने ढंग से उन लोगों को आवंटित किए गए हैं जो इसके लिए हकदार नहीं हैं और इसी तरह के ई-श्रेणी क्वार्टर अभी भी उपलब्ध हैं, जिन्हें मंत्रियों के लिए निर्धारित केंद्रीय पूल में क्वार्टरों के कब्जे को जारी रखने के लिए आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि उन्हें बिहार राज्य की पुरानी गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ही केंद्रीय पूल से ये आवास आवंटित किए गए थे।

8. हमने बार में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। यह विवाद में नहीं है कि ये क्वार्टर अपीलार्थियों को आवंटित किए गए थे जब उन्होंने पुरानी गठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली थी। अपीलार्थियों को सरकार में अपने

मंत्री पद की समाप्ति के कारण आवास खाली करने और संबंधित विभाग को सौंपने के लिए कहा गया है। संबंधित विभाग ने नवगठित गठबंधन सरकार में पहले से ही उन आवासों को मंत्रियों को आवंटित कर दिया गया था। अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील के प्रस्तुतिकरण से यह स्पष्ट है कि वे केंद्रीय पूल के क्वार्टरों पर कब्जा करना जारी रखने के लिए किसी भी कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर रहे हैं जो मंत्रियों के लिए निर्धारित हैं, उनका पूरा तर्क नकारात्मक समानता की अवधारणा पर आधारित है। अपीलार्थियों का यह तर्क है कि डी एंड ई-प्रकार के क्वार्टर हैं जिन पर विधान सभा के कुछ सदस्यों का कब्जा है जो उन क्वार्टरों को प्राप्त करने या उन पर कब्जा करने के हकदार नहीं हैं, लेकिन विभाग द्वारा अवैध रूप से और मनमाने ढंग से आवंटित किए गए हैं। इस प्रकार, केवल नकारात्मक समानता के अनुरोध पर अपीलार्थी विचाराधीन क्वार्टरों पर कब्जा जारी रखने के अपने अधिकार पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं।

9. हमें विदेश संचार निगम लिमिटेड बनाम अजीत कुमार कार ए.

आई. आर. 2009 एस. सी. 34 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों की याद दिलाई जाती है जिसके कंडिका 27 का हिस्सा तैयार संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

“27. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि डी. आर. सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुग्रह का विषय है न कि एक निहित अधिकार और इसलिए विशेष दर पर इस तरह के भत्ते के अनुदान के लिए सरकार के खिलाफ दावा न्यायोचित नहीं है। सी. सी. ए. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 55-ए के संदर्भ में ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों के अधीन डी. आर. का अनुदान केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। डी. ए. के अनुदान के लिए एफ. आर. के नियम 44 ने राज्य पर इसे देने का कोई कर्तव्य नहीं लगाया और यह केवल राज्य को अपने विवेक से अनुकंपा भत्ता देने की शक्ति प्रदान करता है और इसलिए ऐसी शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने के लिए कोई आदेश या कोई अन्य रिट या

निर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी में ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो संरक्षित या लागू करने में सक्षम हो। [एम. पी. राज्य वी. जी. सी. मंडावर राज्य (ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 493) देखें। ”

10. हम ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1937 में प्रतिवेदित किए गए फुलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में नकारात्मक समानता के प्रस्ताव पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी ध्यान देंगे; माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के निम्नलिखित पैराग्राफ इस प्रकार उद्धृत किए गए हैं:-

“13. प्रत्यर्थी डी. एस. लॉन्गिया (उपरोक्त) के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं की गई है। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या धोखाधड़ी को कायम रखना नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 में एक सकारात्मक अवधारणा है। समानता एक विचार है, जिसका अवैध रूप से दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, इसे किसी नागरिक या अदालत द्वारा नकारात्मक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति या समूह के पक्ष में अवैधता और अनियमितता की गई है। व्यक्तियों या न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या गुणा करने या गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या उच्चतर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकते हैं। किसी विशेष पक्ष के पक्ष में एक गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पक्ष को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है। अन्यथा भी अनुच्छेद 14 को बहुत दूर नहीं बढ़ाया जा सकता है अन्यथा यह प्रशासन के कार्य को असंभव बना देगा। [कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1772; पंची देवी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (2009)

2 एससीसी 589:(ए. आई. आर. 2008 एस. सी. (सप) 780); और शांति स्पोर्ट्स क्लब एंड ए. एन. आर. बनामभारत संघ और अन्य। (2009) 15 एससीसी 705]:(ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 433:2009 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 6953)।”

11. हमने पाया है कि विद्वत रिट अदालत ने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग के संपदा अधिकारी द्वारा रिट याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जारी किए गए आक्षेपित पत्रों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अपीलार्थी उन आवासों के कब्जे को जारी रखने के लिए किसी भी कानूनी अधिकार का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं जो स्वीकार्य रूप से केंद्रीय पूल में आते हैं और केवल मंत्रियों को आवंटित किए जाते हैं। कुछ अपात्र, अवैध और मनमाने आवंटन के संबंध में विद्वत रिट अदालत पहले ही अपीलार्थियों की शिकायत का समाधान कर चुकी है, जिन व्यक्तियों का दावा अपीलार्थियों ने किया है।

12. हम विद्वत रिट अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। इन दोनों लेटर्स पेटेंट अपीलों को योग्यता से रहित होने के कारण, तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(राजेन्द्र मेनन, मुख्य न्यायाधीश)

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।